

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

भारतीय बस्ती

बस्ती 15 नवम्बर 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

जलवायु परिवर्तन और मंहगाई

केंद्रीय बैंक व सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के चलते खुदरा मुद्रास्फीति पिछले चोदह महीनों की ऊंचाई पर जा पहुंची है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खुदरा मंहगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के छह फीसदी के संतोषजनक स्तर से ऊपर निकल गई है। आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत रही। ऐसे में खुदरा मंहगाई के आरबीआई द्वारा निर्धारित संतोषजनक स्तर से ऊपर निकल जाने से इस साल दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमोबेश धराशायी हो गई है। दरअसल, खुदरा मंहगाई में यह वृद्धि सब्सिडियों, वसायुक्त वस्तुओं व तेलों की कीमतों में तेजी की वजह से हुई है। जो कि भारत की खाद्य आपूर्ति शृंखला में व्याप्त गहरी संरचनात्मक चुनौतियों का खुलासा करती है। साथ ही स्थिति में सुधार के लिये अविलंब सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत को बताती है। निश्चित रूप से अक्तूबर की खाद्य मुद्रास्फीति दर का इस साल सबसे अधिक 10.87 फीसदी होना नीति-नियंताओं के लिये चिंता का विषय होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह बढ़ती मंहगाई एक महत्वपूर्ण संकेत भी देती है कि अस्थिर भारतीय कीमतों देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिरता को कैसे बाधित कर सकती है। विशेष रूप से टमाटर और तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, कुछ प्रमुख वस्तुओं और आयात की जाने वाली चीजों पर देश की निर्भरता हमारी कमजोरी को ही दर्शाती हैं। इसमें दो राय नहीं कि हर साल वर्षा ऋतु में सब्जी उत्पादक राज्यों में अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के कारण उत्पादन व आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वहीं अनियमित और ज्यादा बारिश से सब्जी व फलों को होने वाले नुकसान न बता दिया है कि जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। जिसकी आशंका हम कई वर्षों से जताते रहे हैं। अब इस चुनौती का युद्ध स्तर पर मुकाबला करने की जरूरत है।

बहरहाल, हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों से सब्सिडियों के उत्पादन व आपूर्ति को कैसे सुरक्षित करें। ऐसे तम में जब कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव नजर आया है, हमें मौसम के चरम में बेहतर उत्पादन देने वाली सब्सिडियों व अन्य फसलों की उन्नत तकनीकें तैयार करनी होंगी। साथ ही बेहतर मंडारण सुविधाएं जुटानी होंगी। जिससे बिचौलियों की मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाकर कृत्रिम मंहगाई को रोकना जा सकेगा। हम व्यावहारिक आयात रणनीति को अपनाने हुए सब्सिडियों व फलों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करेंगे। कालांतर ये प्रयास खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में मददगार होंगे। हमें औद्योगिक उत्पादन में भी तेजी लाने की जरूरत है ताकि लोगों की आय बढ़ने से क्रय शक्ति में इजाजत हो। हालांकि, सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन यह आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। दरअसल, कम वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने में सहायक नहीं हो सकती है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में यह मामूली वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था में सुस्ती को बताती है। निस्संदेह, मुद्रास्फीति में कमी किए बिना सुधार की गति को बनाये रखने में मुश्किल है। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से उपभोक्ता मांग कम हो सकती है। कालांतर इसका असर निवेश पर भी पड़ सकता है। निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक विकास के लिये मुद्रास्फीति के दबावों से उबरने की आवश्यकता है। इसके लिये कृषि उत्पादन व औद्योगिक प्रदर्शन में तेजी लाने की ही जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के बीच सरकार को घरेलू उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। जिससे हमें आपूर्ति शृंखला को अनुकूल बनाने में मदद मिल सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी जरूरी है। बहरहाल, दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता के लिये जरूरी है कि देश बार-बार मुद्रास्फीति में होने वाली बढ़ोतरी को रोकने के लिये कृषि सुधारों को प्राथमिकता दे। जिससे कमजोर आय वर्ग के परिवारों को बढ़ती कीमतों के दबाव से राहत मिल सके।

मंहगाई की बढ़ती मार और सरकार



—रोहित माहेश्वरी—

ऐसे में भारत में मंहगाई बहुत कृषि नियंत्रित कही जा सकती है, लेकिन त्योहार के इन दिनों में मंहगाई आम आदमी के लिए चिंता का कारण बन गई है, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मंहगाई में कुछ कमी आयी है, लेकिन अब भी मंहगाई दर सहन क्षमता के ऊपर है। अक्तूबर में खुदरा मंहगाई दर 6.2 फीसदी रही है। यह बीते 14 माह के उच्चतम स्तर पर है और भारतीय रिजर्व बैंक के 4-5 फीसदी के संतोषजनक स्तर से भी बहुत ज्यादा है। देश में हरी सब्जियों की कीमतें अक्तूबर में ही 42.2 फीसदी तक बढ़ी हैं। खाद्य और शीतल पेय वाले समूह में मंहगाई सितंबर में 8.36 फीसदी रही, लेकिन अक्तूबर में बढ़ कर 9.69 फीसदी तक पहुंच गई। राजधानी दिल्ली और अधिक राजधानी मुंबई में ब्याज खुदरा दर 70-80 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में ही नासिक सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। वहां की मंडियों में भी ब्याज औसतन 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है।

बाजार के जानकारों का आकलन है कि प्याज के दाम 100 रुपए



किलो तक बढ़ सकते हैं और टमाटर इससे भी काफी मंहगा बिक सकता है। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, अनाज, दालें, खाद्य तेल और खेती के लिए अनिवार्य वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। किसानों को रबी फसलें बोनी हैं, लेकिन बाजार में खाद का संकट है। खाद की दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं। खाद की जो बोरी 50 किलो की मिलती थी, वह अब कम कर दी गई है, लेकिन बोरी 300 रुपए तक महंगी कर दी गई है। किसान औसतन सस्ती फसल कैसे बो सकता है और उसे मूल्यतम समर्थन मूल्य कैसे मिल सकता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का आकलन है कि मंहगाई अभी और बढ़ेगी। भारत सरकार और रिजर्व बैंक में मिल कर तय किया जा कि खुदरा मंहगाई दर 4-5 फीसदी के बीच रहनी चाहिए। आदर्श स्थिति 4 फीसदी की है। अभी तक कोशिशें की गई कि मंहगाई वहीं तक सिमट कर रहे, लेकिन अब हरे लोभ दी गई हैं। सितंबर में खुदरा मंहगाई

दर 5.5 फीसदी पर पहुंच गई थी। बढ़ोतरी के संकेत वहीं से मिल गए थे। अब यह मंहगाई दर 6.2 फीसदी हो गई है, जो सर्वाधिक है। ये तमाम आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किए हैं। जो संश्लिष्ट निजी क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनका झटा भिन्न हो सकता है और मंहगाई दर भी ज्यादा हो सकती है। बहरहाल अभी जो चुनाव किए जा रहे हैं, उनमें मंहगाई प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावों में मुनफखोरी की रेडियां की प्रतिद्वंद्विता है अथवा बांटने, कानटे, डरने, मरने की ही चर्चाएं हैं। मंहगाई के अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कभी भी जनादेश तय नहीं होता, जबकि ये आम आदमी की बुनियादी समस्याएं और जरूरतें हैं। एसबीआई रिसर्व के मुताबिक, देश के 23 राज्यों में से उत्तीसगढ़ में बीते एक साल के दौरान, मंहगाई सबसे अधिक 6.4 फीसदी बढ़ी है। माघ में 3 फीसदी, उप्र, बिहार, केरल, तमिलनाडु में 2.3 फीसदी मंहगाई

बढ़ी है। पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं, जहां साल भर में मंहगाई क्रमशः 0.4 फीसदी और 0.7 फीसदी ही बढ़ी है, लेकिन मंहगाई दर 5 फीसदी से अधिक रही है। सिर्फ राजस्थान ही ऐसा इकलौता राज्य है, जहां मंहगाई दर घटी है। देश में पांच राज्य ऐसे हैं, जहां मंहगाई दर 7 फीसदी से ज्यादा रही। ओडिशा 7.5 फीसदी मंहगाई दर के साथ इन राज्यों में शिखर पर है। डाटा में यह भी बताया गया है कि 11 राज्यों में मंहगाई दर 6 फीसदी से कम रही है। बहरहाल अलग अलग किया जा रहा है कि ऐसी बढ़ोतरी के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में मंहगाई दर अंततः 4.8 फीसदी रहेगी, जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य की परिधि में है। गौरतलब यह है कि खाद्य वस्तुओं की मंहगाई दर अक्तूबर में 10.87 फीसदी रही है, जो सितंबर में 9.24 फीसदी थी। बताया जाता है कि मौसम की अनिश्चितता से कई राज्यों में फसलें प्रभावित हुईं। आलू-टमाटर समेत प्रमुख सब्सिडियों के उत्पादन कम

हुए। मांग और आपूर्ति में फासला बढ़ा। बहरहाल सरकारी आंकड़ों में मंहगाई की जो भी तस्वीर सामने आती है, वह आम आदमी को चुभने वाली है। उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद आम आदमी की औसतन आय नहीं बढ़ी, बल्कि बचत भी मात्र 9 फीसदी रह गई है। ऐसे में वह मंहगाई का सामना कैसे करे? खाद्य कीमतों में भी गिरावट आनी चाहिए। कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति तभी उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु या सेवा की प्रमाणी मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है। आपूर्ति की लागत और आपूर्ति की मात्रा मुद्रास्फीति के आपूर्ति-पक्ष की गतिशीलता को निर्धारित करती है। डीजल महंगा होता जा रहा है। गैस एवं उर्वरक की बढ़ती कीमतें इस सेक्टर को मंहगाई से डरा रही हैं। याद रहे कि मंहगा भोजन आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। किसी भी स्थायी मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कृषि उत्पादन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनी व्यापार नीति को सावधानीपूर्वक जांचते रहना चाहिए। साथ ही टमाटर, प्याज और आलू, जैसी अस्थिर सब्सिडियों के लिए बफर स्टॉक बनाया जाए, जिससे किसानों को अधिक पैदावार के दौरान उत्तरी उपज के लिए स्थिर कीमतें प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसके लिए कम लागत पर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कोल्ड स्टोरेज, बुनियादी ढांचे का विस्तार महत्वपूर्ण होगा। इससे सरकार कीमतों को कम करने के लिए जब मांग अधिक हो तब स्टॉक को व्यवस्थित रूप से जारी कर सकती है। वास्तव में, किसी समस्या का

समाधान यह स्वीकार करने से शुरू होता है कि समस्या मौजूद है और मंहगाई केवल राजनीतिक विषय नहीं है। वंचितों को थोड़ी मात्रा में अनाज वितरित करना अर्थव्यवस्था को फिर से घटती पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आम लोगों पर मंहगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं, जो उन्हें गरीबी की ओर धकेलते हैं। अभी लोगों को मंहगाई की मार से कैसे बचाया जाए, यही स्वाल हमारे लिए तात्कालिक महत्व का है। मंहगाई नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बूटि देश में कसल कटाई के चाक की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में इस बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग का विशाल प्रभाव व्यवस्था की डार पर बढ़ना होगा। हम उम्मीद करें कि इन विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से देश में खुदरा मंहगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा और वास्तु वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा मंहगाई लक्ष्य के अनुरूप 4.5 फीसदी तब आनी वर्ष 2025-26 में चार फीसदी के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, लेकिन मुद्रास्फीति विकास के खेती को विभाजित सकती है। अगर मंहगाई बेकाबू हो गई तो आजीवनिक के पास खाद्य दरें बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह अनिवार्य रूप से भारत की विकास दर पर भी असर डालेगा। बढ़ती मंहगाई एवं उच्च मुद्रास्फीति के खतरे को हलके में नहीं लिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर जरूर सोचना चाहिए। अगर मंहगाई को तुरंत लगाने नहीं लगाई गई, तो गरीब व मध्यम वर्ग का जीना निश्चय ही कठिन हो जाएगा।

विकास में बाधक हैं मुफ्त की रेवडियां



—क्षमा शर्मा—

पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मलिककाजुन खड्गे ने केनाईक में अपने ही दल की सरकार की यह कदम उठाते आलोचना की कि जो चुनावी दल है, वह पूरे नहीं किए जा सकते, उन्हें न करें। वजह यह है कि सरकार बन जाने पर उन्हें पूरा करने में कठिनाई आती है। उनका आशय मुक्त की उन योजनाओं से था, जिन्हें पूरा करने में सरकारी खजाने को खाली होने का डर होता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अभी खबर आई ही थी कि वहां सरकारी खजाने का हाल यह है कि सरकारी कमराधारियों को बेतन देने तक के लिए संसाधन जुटाने में दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का सरकार हो है। लेकिन पक्ष-विपक्ष के नेताओं को चुनाव जीतने से मतलब है। सोच लिया जाता है कि बाद की बात में देखेंगे। इसलिए खड्गे के बयान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अरसे से देख रहे हैं कि सभी दल, जनता उन्हें वोटे, वे किसी न किसी तरह चुनाव जीत जाएं, इसके लिए मुफ्त में सब कुछ देने का वादा करते हैं। वे भूल जाते हैं कि अपने ही किए गए वादों के जाल में फंस सकते हैं। फंसते हैं, तभी तो खड्गे ने ऐसा बयान दिया। एक बार तमिलनाडु से आने वाली धर्मेन्द्र साहयिका ने बताया था कि महिने भर का राशन-अनाज, घावल, दालें, तेल, मसाले आदि सब चीजें मुफ्त में हर एक के घर पहुंचा दी जाती हैं। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। चुनावी घोषणापत्र में अनाज दही, मोबाइल, साइडलैप, स्फूटी, लैपटॉप, साइडिंग आदि देने का वादा करते हैं। पक्के घर, बिजली, पानी आदि भी देने के वादे किए जाते हैं। मुफ्त की थिकिसा सुविधा भी। इन दिनों तो युवाओं, हितियों, बुजुर्गों के खतों में सीधे हजारों रुपए भेजने की बातें की जाती हैं। ये पैसे कहा से आएंगे, इसकी चिंता किसी



दल को नहीं होती। सारे पैसे मुफ्त में देने में ही खर्च हो जायेंगे, तो बाकी के कामों का क्या होगा। कोई भी यह नहीं कहता कि लोग परिश्रम करें। है इसकी योजनाएं बनाई हैं कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में काम पर कैसे लगाया जाएगा। वैसे भी अपने वाले कावराव है कि अगर सरकार न बाकरी, पंजी करे न काम। दास मुक्त कह गए सबके दाता रा। यानी कां के लोग और अब सरकारों के भरोसे रही। किसी भी दल को बर्बाद करना हो, तो लोगों को श्रम से मुक्त मोडना और भाग्य के भरोसे रहना सिखा दे। वही अपने यहां हो रहा है। मुफ्त की रेवडियां बांटें और कुछ रास्ता न बचे तो बड़बड़ बिक के सामने कोटाल फैलाकर फंस ले लिया जाए। वेनेजुएला जैसे फलते-फूलते देश की अर्थव्यवस्था पर रेवडियों के कारण किस तरह से बंद हो गई, यह हम सबने देखा। और सोवियत संघ के पतन से भी हमने कुछ नहीं सीखा।

कुछ साल पहले बिजली का बिल बीजेपी सरकार के लिए बिजलीघर गई थी। वहां पान घला कि फोटोकॉपी वाला इस काम को आसानी से करा देता है। कुछ पैसे देने होंगे। बार-बार आने और फिर भी काम न हो पाने के मुकाबले, कुछ पैसे देना उचित लगता है। वहां मुंबई, तो कंठोपमिण्डा एक आदमी से बात कर रहा था। वह आदमी कह रहा था कि पान घला एक कालोमी में उसका पचोस गज का बार मजिल का है। बारों मजिल उसी के पास है। वह चाहता है कि हर मजिल पर एक अलग मीटर लगा दिया जाए, जिससे कि किसी भी मजिल का बिल दो सी

यूनिट से ज्यादा न आए और उसे बिजली का एक पैसे न देना पड़े। यानी कि खर्च तो आठ से यूनिट हो जायें, मगर अलग-अलग मीटरों के कारण उबका बिजली का बिल सपू हो जायें। कान्पुर, दिल्ली की सरकार ने दो सी यूनिट बिजली मुफ्त में दे रही है। यह तो एक उदाहरण है, लम्बे-चौड़े दिल्ली शहर में ऐसा किस्म का दल करते होंगे, इसका अनुमान रखज ही लगाया जा सकता है।

दरअसल, एक बार अगर मुफ्त की कोई योजना शुरू कर दी जाए तो फिर किसी भी दल की हिममत नहीं होती कि वह उसे खत्म कर दे। क्योंकि खत्म करने की विधियों उसके पीछे पड़ जायें और अपने मुकदमा होने पर दल, लोग चुनाव हरा देते हैं। इसके अलावा यह भी होता है कि आने आने किसी को एक रुपया मुफ्त दिया है, तो वह कहता है कि एक रुपया तो पहले से ही मिलता है, वही दे दे तो नया क्या दे रहे हो। वाट तो तब दे, जो ये बताओ कि इस एक रुपए से बढकर किना दो हों। जितना मुफ्त मिलता जाता है, लालच बढ़ता जाता है।

कुछ साल पहले पास ही के उत्तर प्रदेश के शहर में साहित्य उत्सव में गई थी। वहां स्थायी लोग बहुत थे। उनमें से बहुत से गांवों से आया थे। उनका कहना था कि अब गांवों में युवा कम करने को तैयार नहीं है क्योंकि किताबें लोगों को बहुत कुछ मुफ्त मिलता है, तो कोई काम क्यों करे। यह भी बताया कि बहुत से गांव इन्हें होकर, दिन भर जूआ खेलते रहते हैं। चूँकि खाली हैं, तो लडाई-झगडा और अपराधों का ग्राफ भी बढा है। यह सिर्फ एक

स्थान की बात नहीं है। भारत भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब काम करने वाले आसानी से नहीं मिलते। खटाछ-घटाफट के चक्कर में लोग बस बात से आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हें अब खाने-पीने और पेस की दिक्कत नहीं होगी, तो बिना मतलब काम क्यों किया जाए। परिश्रम न होने के कारण गांवों में, कम उम्र में ही वीमार्गियां बढ रही हैं, जिन्हें बड़ी उम्र के रोग काह जाता था।

तमाम बड़े अर्थशास्त्री मुफ्त की योजनाओं को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक मानते हैं, मगर दलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नकली समाजवाद का रोग अपने देश में इस कदर फैला है कि सब कुछ मुफ्त में चाहिए। जबकि एक मशहूर वाक्य है 'दूल्हा इन दूत जी'। यानी कि पूँजीवाज में मुफ्त की इमत नहीं होता। एक तरफ मुफ्त की कैसे बढे, इसके लिए सरकारें रती रहती हैं, मगर सब कुछ मुफ्त-मुफ्त के वादे करके लोगों को परिश्रम से मुँह मोड़ती हैं। बरेचिनि-बरेचिनि का मतलब मात्र बावत है, लालच बढ़ता जाता है, उनके लिए कठिन परिश्रम करना है।

लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी मूल्यवती है कि नारा दिया जायें कि कि जगता मालिक है, लेकिन मालिक बनते ही लोग किसी के लिए काम करने के मुकाबले, मुफ्त की योजनाओं की बात देकर लाते हैं। सारे राजनीतिक दल इसे खूब हवा भी देते हैं। इन्हें बढता जाए और इस देश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देकर उन्हें परिश्रम की तरफ मोड़ा जाए, तभी देश का सही विकास हो सकता है।—लेखिका वरिष्ठ पत्रकार है।

जातियों में उलझी राजनीति



—संजय सक्सेना—

यह बात समझ से परे है कि फिर भाजपा दलों के नेताओं का हिन्दू समाज में पिछड़े और दलित जाति के लोगों की ही चिंता क्यों सताती है। उनका ध्यान उन और दलित मुसलमानों की तरफ क्यों नहीं जाता है जो उच्च श्रेणी के मुसलमानों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हैं। मुसलमानों में दलित और पिछड़े लोगों की पहचान परमांडा समाज के रूप में है। दरअसल भारतीय मुसलमान मुख्यतः तीन जाति समूहों में बंटा हुआ है इन्डोइरानियन,अलफा, और अरजाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह हैं, जिसके अंदर अलग-अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही अरजाल, अलफा, और अरजाल को देखा जाता है, अरजाल में सैयद, शेख, पठान, निज़ा, मुगल जैसी जातियां हैं, जातियां शामिल हैं, मुस्लिम समाज की दलित जातियों की तुलना हिंदुओं की उच्च जातियों से की जाती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं, दूसरा वर्ग है अलफा, इसमें कश्मिरी बौद्ध की जातियां शामिल हैं, अरजाल में वे लोग हैं, जिन्हें खसस तौर पर असिरी, मंगरी, राइन, कुश्नी जैसी कई जातियां शामिल हैं, कुश्नी दल का व्यापार करने वाले और असिरी मुख्य रूप से कपड़ा बनाई के पेस से जुड़े होते हैं, हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोइर, कुमी जैसी जातियों से की जा सकती है, तीसरा वर्ग है अरजाल, इसमें हवालखोर, हवारी, रजजाल जैसी जातियां शामिल हैं, हिंदुओं में मला और काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हवालखोर और कपडा देने का काम करने वाले बौद्ध कहलाते हैं, अरजाल में वे लोग हैं, जिनका पेशा हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लोगों का होता था, इन मुसलमान जातियों का पिछड़ापन आज भी हिंदुओं की समकक्ष जातियों जैसा ही

मुसलमानों में भी जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है, विवाह और पेशे के अलावा मुसलमानों में अलग-अलग जातियों के रीति रिवाज भी अलग-अलग हैं, मुसलमानों में भी लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं, मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर कॉलोनिया बनी हुई दिखाई देती है, कुछ मुसलमान जातियों की कोलीनी एक तरफ बनी हुई है, तो कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ, पिछेमी उत्तर प्रदेश के संमल में तुर्क, लोधी मुसलमान रहते हैं, उनके बीच काफी इतारक है, उनके अलावा अनेक इलाके हैं, राजनीति में भी ये देखा जाता है,अली अनवर कहते हैं कि जिन से लेकर मरने मुसलमान जातियों में बंटा हुआ है, शादी तो छोड़िए, रोटी-बंदी का रिश्ता भी नहीं है,एक दो अपवाद को छोड़कर जातियों के आधार पर कई मजिदें बनाई गई हैं, गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बनाए गए हैं, हलाखखोर, हवारी, रजजाल जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख, पठान जातियों के संसाधन में दफनाने की उगाह नहीं दी जाती, इनके अनुसार, कई बार तो पुरिसर को बुलाना पड़ता है,मुसलमानों में कम से कम 15 जैसी जातियां हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए, मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें आबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन उनसे हवालखोर जैसी जातियों के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता, जिनके उनका पिछड़ापन हिंदू दलितों जैसा है।

इस संकट में प्रो. तनवीर फजल बताते हैं कि धर्म परिवर्तन के समय लोग अपने साथ अपनी जातियां जातियां भी लेकर आए, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने जाति के नहीं छोड़ा, उत्तर प्रदेश के जिन राजपूतों ने मुस्लिम धर्म अपनाने, व अभी भी अपने नाम के साथ बर्हान रखते हैं, खुद को राजपूत मानते हैं, यह भी माना जाता है कि जो कुछ, मुगल और अफगान भारत में आए, उन्होंने अपने लोगों को शासन व्यवस्था में ऊंचा स्थान दिया और वहां के लोगों को कानून निर्माण से देखा, प्रोफेसर फजल के अनुसार ही सरकार के वहां से ही इसकी शुरुआत हुई हो। खैर, यह सब बातें इस विषय के बावजूद जा रही थी क्योंकि हालांकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास पर हमला बोलेते हुए कहा था कि यह लोग मुसलमानों में दलित और पिछड़ों की बात क्यों नहीं करते हैं।

राज्यसभा के पूर्व सांसद और परमांडा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर अंसारी कहते हैं कि

रामायणी, महंत उत्तम दास, पहलवान राजेश्वर दास, महंत रामरसिक शरण, हनुमानाढी के पुजारी रमेश दास, संत विद्याभूषण शरण, महंत अदनीश दास, महंत रामभद्र शरण, महंत कृष्णकुमार दास, महंत अवधकिशोर शरण, महंत मणिपारा दास, महंत रामनारायण दास, महंत गोविंद दास, महंत महेश दास, व्यास श्याम दास, कवन भवन के पुजारी दिनेश जी, संत दास, महंत मनीष दास, पहलवान घनश्याम दास, नंदकुमार मिश्र आदि समेत मंदिर से जुड़े शिष्य-परिकर, अनुयायी उपस्थित रहे।

